



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2003/अग्रहायण 7, 1925

No. 195]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2003/AGRAHAYANA 7, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/73/2003-सीएचपीटी.—चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) द्वारा देय राजस्व भाग अधिकतम 27% को लागत के रूप में मानने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन जारी किए गए नीति निदेश के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा सीसीटीएल के अंतरिम संशोधित दरमान का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/73/2003-सीएचपीटी

आदेश

(नवम्बर, 2003 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) का वर्तमान दरमान दिनांक 6 मार्च, 2002 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित किया था जो भारत के राजपत्र में 15 मार्च, 2002 को अधिसूचित किया गया था। इस दरमान की वैधता 14 सितम्बर, 2003 तक माह निर्धारित की गई थी। प्रशुल्क निर्धारित करते समय इस प्राधिकरण ने सीसीटीएल द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास को देय राजस्व हिस्से का 37.128% उल्लिखित कारणों से लागत तत्व के रूप में मानने से इंकार कर दिया था। तथापि उस समय प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए अपनाए गए तरीके से सीसीटीएल के पास, स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ भुगतने के बाद, वर्ष 2002 में 24.9% राजस्व अतिरिक्त था और वर्ष 2003 के लिए 14.1% राजस्व अतिरिक्त था।

2. सीसीटीएल ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। इसी बीच, पीएसए एसआईसीएल और सीसीटीएल के निजी टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने संबंधी मुद्दे को पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाथ में लिया गया था। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया था और तदनुसार जैसाकि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन यथा अपेक्षित है, पोत परिवहन मंत्रालय ने, इस प्राधिकरण की राय प्राप्त करने के पश्चात्, इस अधिनियम की धारा 111 के अधीन, निदेश जारी किया जिसमें सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क में संशोधन करने का निदेश दिया गया। इस प्राधिकरण ने दिनांक 6 मार्च, 2002 के अपने आदेश में निर्णय ले लिया था और इस आदेश के विरुद्ध सीसीटीएल द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका भी इस प्राधिकरण ने दिनांक 12 अगस्त, 2002 को खारिज कर दी। इस प्रकार, प्रशुल्क परिकलन के लिए राजस्व के हिस्से को लागत के रूप में स्वीकार न करने के बारे में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के विचार इन आदेशों के माध्यम से ही जाने गए हैं। इस प्राधिकरण ने प्रस्तावित नीति निदेश पर, अपेक्षा के अनुसार, विस्तृत प्रतिसाद दिया।

3. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क पर पुनर्विचार करने और संशोधन करने के लिए अपने पत्र सं. पीआर-14019/6/2002-पीजी (I) दिनांक 7 नवम्बर, 2003 द्वारा इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन नीति निदेश जारी किया। सरकार के नीति निदेश में शामिल मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- (i) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के विचारों पर यथोचित रूप से विचार किया गया है।
- (ii) यह विचार किया गया है कि रायल्टी भुगतान, जिसे प्रशुल्क निर्धारण के लिए रायल्टी भुगतान को सीसीटीएल की लागत नहीं माना गया है, के बारे में नीति 29 जुलाई, 2003 तक स्पष्ट नहीं थी, प्रचालकों ने निर्णय लिया कि रायल्टी भुगतान को माध्यम के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए थी और यह तथ्य है कि रायल्टी भुगतान को लागत तत्व के रूप में नहीं मानने से सीसीटीएल को नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति से पत्तनों में निजी भागीदारी के लिए सरकारी नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- (iii) इसलिए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को निदेश देने पर नीति के प्रश्न के रूप में निर्णय लिया गया है।
- (iv) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क पर पुनर्विचार और संशोधन करे ताकि प्रशुल्क निर्धारण के लिए रायल्टी/राजस्व के हिस्से को इस प्रकार लागत के रूप में गणना में लिया जा सके जिससे प्रशुल्क निर्धारण के लिए रायल्टी/राजस्व के भाग को न गिनने से सीसीटीएल को संभावित घाटे से बचा सके बशर्तें सीसीटीएल द्वारा पत्तन को भुगतान की जाने वाली रायल्टी/राजस्व का हिस्सा (कुल 37.138% में से) अधिकतम 27% हो।
- (v) यह व्यवहार, सीसीटीएल के साथ अनुबंध की ऐसी शेष अवधि के लिए भी जारी रहने दिया जाए जो केवल उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।
- (vi) परंतु, इस संबंध में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के अंतिम आदेश तभी जारी किए जाए जब सीसीटीएल उसके द्वारा दायर मामले को वापस ले।

4. यह प्राधिकरण महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अनुसार नीति के प्रश्न पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए जाने वाले निदेशों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य है।

5. सरकार के नीति निदेश का अनुपालन करने के लिए, सीसीटीएल को हमारे द्वारा 11 नवम्बर, 2003 की सलाह दी गई थी कि वह प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में ही अपना प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करे। उनके ध्यान में यह लाया गया था कि इस प्राधिकरण द्वारा 15 मार्च, 2002 को अधिसूचित वर्तमान प्रशुल्क ढाँचा केवल 14 सितम्बर, 2003 तक ही वैध था। सीसीटीएल से यह भी अनुरोध किया गया था कि यह यह बताए कि उसके द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किए गए केस को वापिस लेने की क्या स्थिति है।

6. प्रत्युत्तर में, सीसीटीएल ने दिनांक 11 नवम्बर, 2003 के अपने पत्र द्वारा आश्वासन दिया है कि वह अपना प्रशुल्क आवेदन पत्र महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा नया प्रशुल्क अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर देगा। इसने इस प्राधिकरण से केवल एक अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया है जो केवल 90 दिनों के लिए वैध होगा। तत्पश्चात 27 नवम्बर, 2003 को, सीसीटीएल ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मामले को वापस ले लिया है।

7. सीसीटीएल मामले में सरकार द्वारा दिए गए नीति निदेश को शीघ्रता से लागू करना इस प्राधिकरण के लिए आवश्यक है। चूंकि सीसीटीएल अपना नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय चाहता है और इस कारण उसने अंतरिम प्रशुल्क के लिए प्रार्थना की है, इसलिए इस प्राधिकरण के पास दिनांक 6 मार्च, 2003 के अपने पूर्ववर्ती आदेश में वर्ष 2002 और 2003 के लिए विश्लेषित और स्वीकृत वित्तीय स्थिति पर विश्वास करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। वर्ष 2003 के लिए पहले से स्वीकृत और अनुमत्त किन्हीं अन्य परिमापकों में बदलाव किए बिना और सकल राजस्व के 27% को लागत के रूप में शामिल करते हुए, वर्ष 2003 के पूर्ववर्ती परिकलन को पुनः तैयार किया गया है। सरकार के नीति निदेश में निर्धारित राजस्व के हिस्से और इक्विटी पर स्वीकृत प्रतिलाभ सहित सभी स्वीकार्य लागत के लेखांकन के पश्चात, संशोधित परिकलन (अनुलग्नक - I) से 17.73% राजस्व घाटे का पता चलता है।

8. यदि वास्तविक निष्पादन और निकट भविष्य में प्रत्याशित विकास के संदर्भ से यातायात और लागत अनुमानों को अधुनातन बनाया जाए तो यह ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जैसाकि सीसीटीएल से ऐसा विश्लेषण प्राप्त नहीं हुआ है, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, हमने अपने पूर्ववर्ती आदेश में विचारित स्थिति पर अंतरिम दृष्टिकोण के रूप में विश्वास किया है। चूंकि यह प्रकरण सरकार के नीति निदेश को तत्काल लागू करने हेतु अंतरिम प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए है, इसलिए इस प्राधिकरण को वर्तमान प्रशुल्क में 17% तक वृद्धि करना उचित प्रतीत होता है जिससे सीसीटीएल प्रशुल्क के माध्यम से लागत के रूप में राजस्व का 27% लाभ मिल सकेगा। यह अंतरिम वृद्धि केवल सीमित अवधि के लिए वैध होगी।

9. जैसाकि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, इस प्राधिकरण के दिनांक 6 मार्च, 2002 के आदेश द्वारा निर्धारित प्रशुल्क दिनांक 14 सितम्बर, 2003 तक वैध था। चूंकि सीसीटीएल द्वारा 14 सितम्बर, 2003 के पश्चात वर्तमान दरों की वसूली को जारी रखना निर्विवाद तथ्य है, इसलिए यह प्राधिकरण अब इस वैधता को पूर्व विनिर्दिष्ट तारीख से आगे बढ़ाना चाहता है। अतः संशोधित अंतरिम दरें प्रभावी होने तक वर्तमान दरें वसूल की जाती रहेंगी।

10. हम सीसीटीएल को प्रशुल्क की समीक्षा करने के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह हमारे द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। इसलिए, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम वास्तविक तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर प्रशुल्क निर्धारित करें। सीसीटीएल को अपना प्रस्ताव 15 दिसम्बर, 2003 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए एक बार पुनः सलाह दी जाती है। चूंकि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और इसपर इस प्राधिकरण में कार्यवाही करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए अब निर्धारित अंतरिम दरें 31 जनवरी, 2004 तक अथवा सीसीटीएल से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगी। अंतरिम दरें प्रचालन से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, सिवाय इसके कि यह प्राधिकरण उपर्युक्त प्राधिकृत अवधि को स्पष्ट रूप से और आगे बढ़ाए। अंतिम दरें निर्धारित करते समय, अब निर्धारित अंतरिम दरों पर पुनर्विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रशुल्क समायोजन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, सीसीटीएल अपने बिलों को उपयुक्त ढंग से समायोजित करेगा।

11. परिणामस्वरूप, और ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन, यह प्राधिकरण सीसीटीएल के वर्तमान दरमान में 31 जनवरी, 2004 तक अथवा इस मामले में अंतिम आदेश पारित करने के समय पुनर्विचार कर अंतिम आदेश पारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम आधार पर सभी मदों में 17% की वृद्धि का अनुमोदन करता है ताकि सीसीटीएल को, 31 जनवरी, 2004 तक या अंतिम आदेश पारित किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रशुल्क के माध्यम से 27% राजस्व-भाग लागत के रूप में मिलने हेतु सरकार के निदेशों को लागू किया जा सके, बशर्तें इस मामले में अंतिम आदेश पारित करते समय उसकी समीक्षा की जाए।

12. सीसीटीएल का अंतरिम संशोधित दरमान इस आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना पर तुरन्त प्रभावी होगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/IV/143/03-असाधारण]

अनुलग्नक - I

चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का लागत विवरण वर्ष 2003 के लिए अंतरिम आदेश

(राशि हजार रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2003
I	टीईयू में थ्रुपुट	484,395
	राजस्व	
	सकल राजस्व	1,295,639
	घटाएं : सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन जारी किए गए निदेश के अनुपालन में सकल राजस्व का 27% राजस्व हिस्सा लागत के रूप में माना गया है।	349,823
	जोड़ (I)	945,816
II	प्रचालन व्यय	
	प्रचालन और प्रत्यक्ष मजदूरी	104,599
	अनुरक्षण मजदूरी	17,213
	उपस्कर चालन लागत	138,353

(1)	(2)	(3)
	प्रचालन उपस्कर मूल्यहास	
	अन्य व्यय	153,353
	टीएसए शुल्क - पी एण्ड ओ पत्तन	165,225
	उप जोड़	0
	उपरिव्यय	578,744
	प्रबंधन और प्रशासन मजदूरी	
	गैर-प्रचालन मूल्यहास	18,875
	सामान्य उपरिव्यय	40,054
	आरंभिक अग्रिम भुगतान बट्टे खाते डालना	42,696
	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए उपस्कर	3,525
	उप जोड़	82
	जोड़ (II)	105,142
III	अधिशेष (I-II)	683,885
IV	वित्तपोषण प्रभार	261,931
	ऋणों पर ब्याज/वित्तपोषण लागत	
	वापसी अदायगी पर विदेशी मुद्रा हानियाँ	191,707
	जोड़ (IV)	0
V	वित्तपोषण प्रभारों के पश्चात अधिशेष (III-IV)	191,707
VI	30वें वर्ष के अंत में प्राप्य राशि को वापस खाते में डालना (12% की दर से बट्टा)	70,224 7,496
VII	जमा खाते में वापसी के बाद निवल अधिशेष/(कमी) (V+VI)	
VIII	इक्विटी शेयर	77,720
	उधार ली गई राशि	1,533,793
IX	लगभग 80% के क्षमता उपयोग से संबद्ध 20% की दर से इक्विटी शेयर पर प्रतिलाभ	1,595,475
X	ब्याज, जमा खाते में वापस राशि और आय के पश्चात निवल अधिशेष	245,407
XI	इक्विटी और वास्तविक ब्याज पर प्रतिलाभ की अनुमति के पश्चात निवल राजस्व के प्रतिशत के रूप में निवल अधिशेष/कमी	(167,687) -17.73%

नोट :

- (1) ध्रुपुट, राजस्व अनुमान और यहाँ विचारित सभी लागत आँकड़े हमारे आदेश सं. टीएमपी/73/2001 दिनांक 6 मार्च, 2003 के अनुसार हैं।
- (2) सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन जारी किए गए निदेश के अनुपालन में सकल राजस्व का 27% राजस्व हिस्सा लागत के रूप में माना गया है।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th November, 2003

No. TAMP/73/2003-CHPT.—In compliance with the policy direction issued by the Government of India, Ministry of Shipping under Section 111 of the MPT Act, 1963 to treat maximum of 27% of revenue share payable by the Chennai Container Terminal Limited (CCTL) as cost and in exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves an interim revised Scale of Rates of CCTL as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**No. TAMP/73/2003-CHPT****ORDER**

(Passed on this 27th day of November 2003)

The existing Scale of Rates of the Chennai Container Terminal Limited (CCTL) was approved by this Authority vide its Order dated 6 March 2002 which was notified in the Gazette of India on 15 March 2002. The validity of this Scale of Rates was till 14 September 2003. While fixing the tariff, 37.128% of revenue share payable by CCTL to the Chennai Port Trust was not allowed by this Authority as a cost element for stated reasons. However, the approach adopted to fix the tariff at that time has allowed CCTL to have a revenue surplus of 24.9% for the year 2002 and 14.1% for the year 2003 after meeting admissible cost and permissible return.

2. The CCTL filed a writ petition against this Order before the Hon'ble High Court of Delhi. In the meanwhile, the issue relating to tariff fixation for the private terminals of PSA SICAL and CCTL was taken up by the Government of India in the Ministry of Shipping. It was decided by the Ministry of Shipping to permit revision of tariff in the case of CCTL and accordingly as required under section 111 of the MPT Act, the Ministry of Shipping, after seeking the views of this Authority, has issued a direction under section 111 of the Act directing revision of tariff in the case of CCTL. This Authority had taken a stand in the matter vide its Order dated 6 March 2002 and a review petition filed by the CCTL against this Order was also rejected by this Authority on 12 August 2002. Thus, the views of the TAMP about not admitting revenue share as cost for computation of tariff are known through these orders. This Authority, as required, had given an elaborate response to the proposed policy direction.

3. The Government of India in the Ministry of Shipping vide its letter No. PR-14019/6/2002-PG(1) dated 7 November 2003 issued a policy direction to this Authority under section 111 of the MPT Act for reviewing and revising tariff in the case of CCTL. The salient points contained in this policy direction of the Government are given below.

- (i). The views of TAMP have been duly considered.
- (ii). It has been considered that the policy about royalty payment being not taken as cost of CCTL for tariff fixation was not cleared till 29 July 2003, operators taking a stand that royalty payment was to be allowed a pass through and the fact that not permitting royalty payment as an element of cost has resulted in losses to CCTL which situation is likely to have adverse impact on policy of Government for private participation at ports.
- (iii). It has, therefore, been decided as a question of policy to direct TAMP.
- (iv). TAMP may review and revise tariff in the case of CCTL so as to take into account royalty/revenue share as cost for tariff fixation in such a manner as to avoid likely loss to CCTL on account of the royalty/revenue share not being taken into account for tariff fixation, subject to a maximum of 27% (out of total 37.138%) royalty/revenue sharing being paid by them to the Port.
- (v). This treatment may continue to be allowed for such remaining period of agreement with CCTL as may be necessary for the above purpose only.
- (vi). The final orders of TAMP in this regard, however, may be issued after the case filed by CCTL is withdrawn by them.

4. In terms of Section 111 of the MPT Act, this Authority in discharge of its functions is bound by the directives on question of policy as the Central Government may give in writing from time to time.

3572-6/10-3

5. In order to comply with the policy direction of the Government, the CCTL was advised by us on 11 November 2003 to submit its tariff proposal in the proforma prescribed by this Authority for submission of tariff proposals. It was brought to their notice that the present tariff structure notified by this Authority on 15 March 2002 was valid only till 14 September 2003. The CCTL was also requested to inform about the status of withdrawing the case filed by it before the Hon'ble High Court of Delhi.
6. In response, the CCTL vide their letter dated 11 November 2003 has assured to submit its tariff application within 15 days of the new tariff notified by TAMP. It has requested this Authority to pass only an interim order which will be valid for 90 days. Subsequently on 27 November 2003 the CCTL informed us that they had withdrawn the case filed by them in the High Court of Delhi.
7. It is necessary for this Authority to expeditiously implement the policy direction given by the Government in the CCTL case. Since the CCTL wants time to frame its fresh proposal and hence prayed for interim tariff, this Authority is left with no other alternative but to rely on the financial position for the years 2002 and 2003 analysed and accepted in our earlier Order dated 6 March 2003. Without altering any other parameters admitted and allowed earlier for the year 2003 and by including 27% of the gross revenue as cost, the earlier calculation for the year 2003 has been re-worked. The revised calculation (Annex-I) discloses a deficit of 17.73% of revenue after accounting for all admissible cost, including the revenue share prescribed in the policy direction of the Government and permissible return on equity.
8. It would have been more appropriate if the traffic and cost projections are updated with reference to the actual performance and anticipated development in near future. Since such analysis is not received from the CCTL, as mentioned earlier, we relied on the position considered in our earlier order as an interim approach. Since this is a case of fixation of interim tariff for immediate implementation of the policy direction of the Government, this Authority finds it reasonable to increase the existing tariff by 17% which will give CCTL the benefit of recovering 27% of revenue share as cost through tariff. This interim relief will be valid for a limited period.
9. As has already been mentioned, the tariff fixed by this Authority vide its order dated 6 March 2002 was valid till 14 September 2003. Since the continued levy of the existing rates made by CCTL after 14 September 2003 is a fait-accompli, this Authority is now willing to extend the validity beyond the earlier stipulated date. The existing rates will, therefore, continue to be levied till the revised interim rates come into effect.
10. The CCTL has already been advised by us to file its proposal for review of tariff. This is necessary for us to fix tariff based on realistic facts and figures. The CCTL is once again advised to submit its proposal on or before 15 December 2003. Since submission of such proposal and its processing in this Authority will take some time, the interim rates fixed now will remain valid till 31 January 2004 or till final Order is passed by this Authority in response to proposal to be received from CCTL whichever is earlier. The interim rates will automatically cease to be in operation unless an explicit extension is given by this Authority beyond the period as authorised above. While fixing final rates, the interim rates fixed now will be reviewed and if necessary tariff adjustment with retrospective effect will have to be made. In the event, the CCTL will adjust its billings suitably.
11. In the result, and subject to the observations made above, this Authority approves on an interim basis an across-the-board increase of 17% over the existing Scale of Rates of the CCTL so as to implement the directive of the Government to allow CCTL through tariff 27% revenue share as cost, till 31 January 2004 or till final order is passed, whichever is earlier, subject to review while passing final order in this case.
12. The interim revised Scale of Rates of CCTL will come into effect immediately on notification of this Order in the Gazette of India.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT III/IV/143/03-Exty.]

COST STATEMENT OF THE CHENNAI CONTAINER TERMINAL LIMITED
INTERIM ORDER FOR THE YEAR 2003

(Amount in Rs. 000)

Sr. No.	Particulars	2003
	Throughput in TEUs	484,395
I	REVENUE	
	Gross Revenue	1,295,639
	Less: Revenue share of 27% of the gross revenue treated as cost in compliance with the direction issued by the Government under Section 111 of the MPT Act.	349,823
	TOTAL (I)	945,816
II	OPERATING EXPENSES	
	Operating & Direct Labour	104,599
	Maintenance Labour	17,213
	Equipment Running Costs	138,353
	Operations Equipment Depreciation	153,353
	Other Expenses	165,225
	TSA Fees - P&O Ports	0
	Sub Total	578,744
	OVERHEADS	
	Management and Administration Labour	18,785
	Non-operating Depreciation	40,054
	General Overheads	42,696
	Preliminary Upfront Payment write off	3,525
	Equipment written off during the year	82
	Sub Total	105,142
	TOTAL (II)	683,885
III	SURPLUS (I-II)	261,931
IV	FINANCING CHARGES	
	Interest on Loans/ Financing Costs	191,707
	Forex Losses on repayment	0
	TOTAL (IV)	191,707
V	SURPLUS AFTER FINANCING CHARGES (III-IV)	70,224
VI	Credit back of the amount receivable at the end of the 30th year (Discounted @ 12%)	7,496
VII	NET SURPLUS/(DEFICIT) AFTER THE CREDIT BACK (V+VI)	77,720
VIII	Equity Share	1,533,793
	Borrowed Funds	1,595,475
IX	Return on Equity Share @ 20% linked to capacity utilisation of around 80%	245,407
X	NET SURPLUS/DEFICIT AFTER INTEREST, CREDIT BACK AMOUNT AND RETURN	(167,687)
XI	NET SURPLUS/DEFICIT AS A PERCENTAGE OF NET REVENUE AFTER ALLOWING RETURN ON EQUITY AND ACTUAL INTEREST	-17.73%

Note:

- (1). Throughput, gross revenue estimates and all the cost figures are retained as per our Order number TAMP/73/2001 dated 6 March 2002.
- (2). Revenue share of 27% of the gross revenue has been treated as cost in compliance with the direction issued by the Government under Section 111 of the MPT Act.